

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 19 अगस्त, 2010

संख्या: वि०स०/1-37/2010.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 19) जो दिनांक 19 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान का समुचित स्तरमान सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों के संरक्षण हेतु, राज्य स्तर पर विनियामक आयोग और विनियामक तंत्र की स्थापना करने तथा उससे संबन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 है ।

संक्षिप्त नाम
और लागू
होना ।

(2) यह हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को लागू होगा ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं ।

- (क) "आयोग" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;
- (ख) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसका अध्यक्ष इसके अन्तर्गत है ;
- (ग) "प्राइवेट शिक्षा संस्था" से, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों (स्कूलों) के सिवाय, राज्य में समस्त प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं अर्थात् महाविद्यालय, शिक्षा के व्यावसायिक महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा के संस्थान, प्रबन्धन, विधि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फार्मसी, सह-चिकित्सीय संस्थाएं और विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस या उच्चतर विद्या की कोई अन्य शिक्षा संस्थाएं अभिप्रेत हैं ;

- (घ) “विनियम” से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ङ) “विनियामक निकाय” से इस प्रयोजन के लिए स्थापित कोई राज्य या केन्द्रीय कानूनी विनियामक निकाय अभिप्रेत है ;
- (च) “छात्र” से किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने वाला प्राइवेट शिक्षा संस्था में प्रविष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (छ) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;
- (ज) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और
- (झ) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।

आयोग की
स्थापना ।

3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, राज्य में विनियामक तंत्र उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए और प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रमों का समुचित स्तरमान सुनिश्चित करने के प्रयोजन तथा छात्रों के हितों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार और केन्द्रीय विनियामक निकायों के मध्य एक अन्तराणीक बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग की स्थापना कर सकेगी ।

(2) आयोग शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

आयोग की
संरचना ।

4. (1) आयोग, अध्यक्ष तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों में से या उनमें से जो तीन वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव या इससे ऊपर रहे हों, या जिन्होंने भारत सरकार में तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए समतुल्य पद धारित किया हो, में से अधिकतम दो पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्यों से गठित होगा ।

(2) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जांच समिति की सिफारिशों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता/लेती; जो भी पूर्वतर हो, की जाएगी और ऐसा अध्यक्ष या ऐसे सदस्य, पैंसठ वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अध्यक्षीन, दूसरी पदावधि के लिए पात्र हो सकेंगे:

परन्तु पदावधि की समाप्ति के पश्चात्, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य किसी भी प्राइवेट शिक्षा संस्था या इसके सहायक कार्यालयों या कम्पनियों में दो वर्ष की अवधि के लिए आगामी नियोजन या किसी कर्तव्य भार के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) जांच समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्:—

- (i) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार — अध्यक्ष;
- (ii) प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) — सदस्य; और हिमाचल प्रदेश सरकार
- (iii) प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा) — सदस्य सचिव । हिमाचल प्रदेश सरकार

सदस्य का
हटाया जाना ।

5. (1) किसी भी सदस्य को, इस धारा के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, अपने पद से हटाया नहीं जाएगा ।

(2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी भी सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि—

- (क) वह सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो; या
- (ख) वह ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित हो; या
- (ग) वह शारीरिक और मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो; या
- (घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
- (ङ) उसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है, जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या
- (च) वह सिद्ध कदाचार का दोषी हो; या
- (छ) वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा हो:

परन्तु किसी भी सदस्य को खण्ड (घ), (ङ), (च) या (छ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक इस प्रयोजन के लिए कोई जांच न की गई और सदस्य को अपनी प्रतिरक्षा का अवसर न दे दिया गया हो।

6. (1) आयोग का एक सचिव होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, नियुक्त किया जाएगा।

आयोग के
अधिकारी और
अन्य कर्मचारी।

(2) आयोग, राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जैसे यह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा ।

(3) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा के निबधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं ।

बैठकें ।

7. आयोग, ऐसे समय और स्थान पर, उतनी बार, जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगा तथा ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

निधि ।

8. आयोग एक निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रति वर्ष कुल फीस का, ऐसा प्रतिशत, जो आयोग द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाए; परन्तु यह कुल फीस के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त ऋण, जो तीन वर्षों के भीतर प्रतिसंदेय होगा;

(ग) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त दान और अन्य कोई अनुदान; और

(घ) शास्तियों के रूप में प्राप्त समस्त रकम ।

आयोग की शक्तियां और कृत्य ।

9. (1) यह सुनिश्चित करना आयोग का कर्तव्य होगा कि प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रम, अर्हित शिक्षकों और अवसंरचना के स्तरमान सन्धियों के अनुसार, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विनियामक निकायों द्वारा या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखे जा रहे हैं । शिक्षा संस्था द्वारा अधिकथित स्तरमानों को पूरा करने में विफलता की दशा में, आयोग को अधिनियम की धारा 11 के

अधीन शिक्षा संस्थाओं पर शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी और संस्था द्वारा स्तरों को पूरा करने में क्रमवार विफलता की दशा में आयोग, राज्य सरकार/विनियामक निकाय को किसी संस्था को बंद करने की सिफारिश कर सकेगा ।

(2) आयोग सुनिश्चित करेगा कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, राष्ट्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा में या किसी अन्य परीक्षा में प्राप्त योग्यता (मैरिट) पर आधारित है और जहां पर राष्ट्रीय स्तर की संयुक्त प्रवेश परीक्षा या राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा नहीं है, वहां योग्यता (मैरिट), सर्वथा अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जाएगी ।

(3) आयोग, छात्रों और माता-पिता की शिकायतों की प्राप्ति और उनके निवारण के लिए, समुचित क्रिया प्रणाली विकसित करेगा और प्राइवेट संस्थाओं को आयोग को, रिपोर्ट की गई शिकायतों के निवारण के लिए, एक समुचित शिकायत निवारण क्रिया प्रणाली स्थापित करने हेतु निदेश कर सकेगा । ऐसी शिकायतों को, आयोग द्वारा नियत समय के भीतर, संस्था द्वारा ऐसी शिकायत के निवारण हेतु उठाए गए कदमों के विवरण सहित, निवारण किया जाएगा ।

(4) आयोग जब कभी अपेक्षित हो, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगा और प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित कर सकेगा ।

(5) आयोग को प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में फीस का अनुश्रवण और विनियमन करने की शक्ति होगी ।

10. (1) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-

आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां ।
1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

- (ख) किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य अन्य भौतिक पदार्थ का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;
- (ग) शपथ—पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
- (घ) किसी लोक अभिलेख को मांगना;
- (ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
- (च) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना; और
- (छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही, सुनवाई या विषय में ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्तियां होंगी जैसा आयोग समुचित समझे ।

(3) आयोग अपने समक्ष कार्यवाहियों में छात्रों तथा माता—पिता के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, जैसा वह उचित समझे, प्राधिकृत कर सकेगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन समस्त विवाद, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 37 के उपबन्धों के अनुसार संक्षेपतः विनिश्चित किए जाएंगे । 1908 का 5

शास्तियां ।

11. (1) आयोग, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी उपबन्ध या आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के लिए, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती उल्लंघन के लिए अधिकतम शास्ति, पांच करोड़ रूपए होगी :

परन्तु तब तक कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक सम्बद्ध संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति, सम्बद्ध शिक्षा संस्था से विन्यास निधि या किसी अन्य निधि से या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी ।

आयोग के
लेखे और
संपरीक्षा ।

12. (1) आयोग अपने लेखों को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में रखेगा, जैसी विहित की जाए ।

(2) आयोग के लेखों की, भारत के नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक संपरीक्षा करवाई जाएगी और आयोग, संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा ।

वार्षिक
रिपोर्ट ।

13. (1) आयोग, यथाशीघ्र, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का विवरण दर्शाती एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ऐसी तारीख को और ऐसे प्ररूप में, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जैसी विहित की जाए और राज्य सरकार ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को इसकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।

(2) आयोग प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को आयोग के संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति भेजेगा और राज्य सरकार ऐसे लेखों को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।

क्षतिपूर्ति ।

14. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां आयोग के अध्यक्ष, किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध न होंगी ।

सदस्यों और
कर्मचारियों
का लोक
सेवक होना ।
1860 का 45

15. आयोग के सदस्य और अन्य कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

निर्देश जारी करने की शक्ति ।

16. राज्य सरकार, आयोग को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जो इसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और आयोग ऐसे समस्त निर्देशों को कार्यान्वित करेगा ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

17. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबन्धों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के उससे असंगत होते हुए भी, प्रभाव होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

18. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव की सेवा के निबन्धन और शर्तें ;
- (ख) आयोग के आदेशों और विनिश्चयों तथा इसके द्वारा जारी लिखतों के अधिप्रमाणन की रीति ;
- (ग) प्ररूप और रीति जिसमें धारा 12 के अधीन आयोग द्वारा लेखों का अनुरक्षण किया जाएगा ;
- (घ) धारा 11 के अधीन शास्ति की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तथा रीति, जिसमें ऐसी शास्ति अधिरोपित की जानी है; और
- (ङ) ऐसे अन्य मामले जो आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित हों ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

19. आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए विनियम बना सकेगी ।

विधान सभा
में रखे जाने
वाले नियम
और विनियम।

20. इस अधिनियम की धारा 18 और 19 के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और विनियम, इनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे ।

कठिनाइयाँ दूर
करने की
शक्ति।

21. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई दूर करने के प्रयोजन हेतु इसे आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मानव के चहुंमुखी विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यह राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है। अच्छी प्रगति के लिए, युवा व्यक्तियों की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में अवश्य पहुंच होनी चाहिए जो विशिष्टतः व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए परिष्कृत स्तरमान बनाए रखती हैं। विद्यालय (स्कूल) स्तर से परे शिक्षा प्रसुविधाओं तक पहुंच हेतु बढ़ती मांग के कारण, यह देखा गया है कि महाविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय और संस्थाएं, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाती हैं, राज्य में प्रचुर मात्रा में स्थापित हो रही हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में स्थापित प्राइवेट रूप से प्रबन्धित शिक्षा संस्थाएं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सम्बन्धित विनियामक निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करती है, एक ऐसा विधान अधिनियमित करने की नितान्त आवश्यकता है जो एक विनियामक आयोग की स्थापना के लिए उपबन्ध करता हो जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के समुचित स्तरमान बनाए रखे गए हैं और ऐसी संस्थाओं में प्रविष्ट छात्रों के हित भी सुरक्षित हैं।

आयोग के पास, इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली की बाबत छात्रों या उनके माता-पिता द्वारा आयोग के समक्ष दर्ज की जा सकने वाली शिकायतों और परिवादों को समयबद्ध रीति में प्राप्त करने और उनका निवारण करने की शक्ति होगी। आयोग के पास प्राइवेट रूप से प्रबन्धित शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्धित विनियामक निकाय के दिशानिर्देशों और आयोग द्वारा इसमें निहित शक्तियों के फलस्वरूप जारी किए जा सकने वाले किसी निदेश के उल्लंघन के लिए पांच करोड़ रुपए तक की शास्ति अधिरोपित करने का प्राधिकार होगा। इस प्रकार एक ऐसा विधान लाने का विनिश्चय किया गया है जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करता हो।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(ईश्वर दास धीमान)

प्रभारी मन्त्री।

शिमला

तारीख :....., 2010.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 8 आयोग को सरकारी ऋण उपलब्ध करवाने का उपबन्ध करता है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 3, 4 और 6 आयोग स्थापित करने तथा विनियामक आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिए हैं। इस प्रकार, आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन तथा भत्तों पर उपगत किया जाने वाला व्यय, विधेयक के खण्ड 8 के अधीन स्थापित की जाने वाली निधि से पूरा किया जाएगा। इसलिए इससे राजकोष पर कोई व्यय उपगत नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विधेयक के खण्ड 18 और 19 राज्य सरकार और आयोग को क्रमशः नियम और विनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

Bill No. 19 of 2010

**THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL
INSTITUTIONS (REGULATORY COMMISSION) BILL,
2010**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for establishment of the Regulatory Commission and Regulatory mechanism in the State for the purpose of ensuring appropriate standard of admission, teaching, examination, research and protection of interest of students in the Private Educational Institutions and for matters connected therewith or incidental thereto;

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title
and
application.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010.

(2) It shall apply to the Private Educational Institutions in the State of Himachal Pradesh.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Commission” means the Regulatory Commission established under section 3 of this Act;
- (b) “member” means a member of the Commission and includes the Chairperson;
- (c) “Private Educational Institutions” means all the private educational institutions in the State *viz.* degree colleges, professional colleges of Education, Institutes of Technical Education, Management, Law, Engineering, Medicine,

Pharmacy, Paramedical Institutions and Universities, deemed Universities, Centres of Excellence or any other educational institutions of higher learning, except schools affiliated to any recognized Board of School Education;

- (d) “regulations” means regulations made by the Commission under section 19 of this Act;
- (e) “Regulatory body” means any State or Central Statutory Regulatory Body set up for the purpose;
- (f) “student” means a person enrolled in the Private Educational Institution for pursuing a course of study for the award of a degree, diploma, certificate or other academic distinction;
- (g) “University Grants Commission” means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956;
- (h) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act; and
- (i) “State Government” means the Government of Himachal Pradesh.

3. (1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, establish the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission for the purpose of providing a regulatory mechanism in the State and for working as an interface between the State Government and the Central Regulatory Bodies for the purpose of ensuring appropriate standards of admission, teaching, examination, research, extension programmes and protection of the interest of the students of the Private Educational Institutions. Establishment of Commission.

(2) The Commission shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The headquarters of the Commission shall be at such place as may be notified by the State Government.

Composition
of
Commission.

4. (1) The Commission shall consist of a Chairperson and maximum of two full time or part time members from amongst persons of eminence in the field of higher education or who have remained Principal Secretary or above to the Government of Himachal Pradesh or held equivalent post in the Government of India for a period of three years or more.

(2) The Chairperson and members of the Commission shall be appointed by the State Government, on the recommendations of a Search Committee, for a period of three years or until he or she attains the age of 65 years, whichever is earlier, and such Chairperson or members may be eligible for a second term subject to the upper age limit of 65 years:

Provided that after the expiry of the term of office, the Chairperson or the member, as the case may be, shall be ineligible for further employment or any assignment in any of the Private Educational Institutions or its associate offices or companies for a period of two years.

(3) The Search Committee shall consist of the following, namely:—

- (i) Chief Secretary to the Government— Chairperson; of Himachal Pradesh
- (ii) Principal Secretary (Technical Education)— Member; and to the Government of Himachal Pradesh
- (iii) Principal Secretary (Higher Education)— Member- Government of Himachal Pradesh Secretary.

Removal of
member.

5. (1) No member shall be removed from office except in accordance with the provisions of this section.

(2) the State Government may, by order, remove from office any member, if he—

- (a) has been adjudged an insolvent by the competent court; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

- (c) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or
- (f) has been guilty of proven misbehavior; or
- (g) has failed to discharge his duties:

Provided that no member shall be removed from his office on any ground specified in clauses (d), (e), (f) or (g) unless an enquiry has been conducted for this purpose and the member has been given an opportunity to defend himself.

Officers and other employees of the Commission.

6. (1) There shall be a Secretary of the Commission who shall be appointed by the State Government in consultation with the Commission on such terms and conditions, as may be prescribed.

(2) The Commission may appoint such officers and employees as it considers necessary, for the efficient performance of the functions of the Commission, after approval of the State Government.

(3) The terms and conditions of service of the officers and employees of the Commission shall be such as may be prescribed.

Meetings.

7. The Commission shall meet, as often as may be necessary, at such time and place and observe such procedure, as may be prescribed by the regulations.

Fund.

8. The Commission shall establish a fund to which shall be credited—

- (a) by the Private Educational Institutions such percentage of total fees every year as may be assessed by the Commission from time to time but not exceeding one percent of the total fees;

- (b) loan from the State Government which will be repayable within three years;
- (c) any other grants received from any other source; and
- (d) all sums received by way of penalties.

Powers and
functions of
the
Commission.

9. (1) It shall be the duty of the Commission to ensure that standards of admission, teaching, examination, research, extension programme, qualified teachers and infrastructure, are being maintained by the Private Educational Institutions in accordance with the guidelines issued by the Regulatory Bodies of the Central Government or the State Government or by the Central Government or the State Government from time to time. In case of failure of the Educational Institution to meet the standards laid down, the Commission shall have the power to penalize the Educational Institutions under section 11 of the Act and in case of successive failure of an Institution to meet the standards, the Commission may recommend to the State Government/Regulatory Body for the winding up of the Institution.

(2) The Commission shall ensure that the admissions in the Private Educational Institutions are based on merit achieved in National Common Entrance Test or the State Common Entrance Test or any other Test as notified by the State Government and where there is no National level Common Entrance Test, or State level Common Entrance Test or any other Test, the merit shall be determined strictly on the basis of the marks obtained in the qualifying examination.

(3) The Commission shall develop an appropriate mechanism for receipt and redressal of grievances of students and parents, and direct the private institution to set-up a proper Grievances Redressal mechanism for redressal of complaints reported to the Commission. Such complaints shall be redressed within the time fixed by the Commission with details of the steps taken by the institution to redress such complaint.

(4) The Commission may conduct inspections of Private Educational Institutions as and when required and may form expert committees, for inspections of Private Educational Institutions.

(5) The Commission shall have the power to monitor and regulate fees in Private Educational Institutions.

10. (1) The Commission shall, for the purposes of any inquiry or proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely :—

Procedure and powers of the Commission.

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning of any public record;
- (e) issuing commission for the examination of witnesses;
- (f) reviewing its decisions, directions and orders; and
- (g) any other matter which may be prescribed.

(2) The Commission shall have the powers to pass such interim order in any proceeding, hearing or matter as the Commission may consider appropriate.

(3) The Commission may authorize any person, as it deems fit, to represent the interest of the students and parents in the proceedings before it.

(4) All disputes under this Act shall be decided summarily in accordance with the provisions of Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908.

5 of 1908

11. (1) The Commission may, for the contravention of any of the provision of this Act or the rules or regulations made thereunder, or

Penalties.

directions issued by the Commission, impose penalty, in such manner, as may be prescribed, but not exceeding one crore rupees:

Provided that the maximum penalty for a second or subsequent contravention shall be five crore rupees :

Provided further that no penalty shall be imposed unless the institution concerned is given an opportunity of being heard.

(2) The penalty imposed under sub-section (1) shall be recoverable from the endowment fund or any other fund or as arrear of land revenue from the Educational Institution concerned.

Accounts
and audit of
the
Commis-
sion.

12. (1) The Commission shall maintain its accounts in such form and in such manner, as may be prescribed.

(2) The accounts of the Commission shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India and the Commission shall send a copy of the audit report to the State Government.

Annual
report.

13. (1) The Commission shall, as soon as may be, after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government, before such date and in such form, as may be prescribed, a report giving an account of its activities during the previous year and the State Government shall cause every such report to be laid before the Legislative Assembly, as soon as may be, after its receipt.

(2) The Commission shall send a copy of the audited annual accounts of the Commission to the State Government every year, and the State Government shall cause such accounts to be laid before the Legislative Assembly.

Indemnity.

14. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against Chairperson, any member, officer or employee of the Commission in respect of anything which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Members
and
employees
to be public
servants.

15. The members and other employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

16. The State Government may issue such directions to the Commission as in its opinion, are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act and the Commission shall give effect to all such directions.

Power to issue directions.

17. The provisions of this Act or rule or order made thereunder, shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

Act to have overriding effect.

18. (1) The State Government may, by notification publish in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Power to make rules.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the terms and conditions of service of the Chairperson, the members and the Secretary of the Commission;
- (b) mode of authentication of the orders and decisions of the Commission and instruments issued by it;
- (c) the form and manner in which the accounts shall be maintained by the Commission under section 12;
- (d) the minimum and maximum limit of the penalty under section 11 and the manner in which such penalty is to be imposed; and
- (e) such other matters as may be required for proper functioning of the Commission.

19. The Commission may, with the prior approval of the State Government, make regulations to carry out the provisions of this Act.

Power to make regulations.

20. Every rule and regulation made under sections 18 and 19 of this Act shall respectively be laid, as soon as may be, after these are made, before the Legislative Assembly.

Rules and regulations to be laid in the Legislative Assembly.

21. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty:

Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is very important for the all round development of a human being and is a most important factor in the socio-economic development of a nation. In order to progress well, young people must have access to educational institutions that maintain quality standards particularly for professional courses. Due to increasing demand for access to education facilities beyond school level, it is seen that degree colleges, private universities and institutions that run professional courses are proliferating in the State.

In order to ensure that the privately managed educational institutions that are established in the State, function in conformity with the guidelines issued by the related regulatory bodies of the Central and the State Governments, there is urgent need to enact legislation that provides for the establishment of a Regulatory Commission that will ensure that appropriate standards of admission, teaching, examination and research are maintained and the interest of students enrolled in such institutions is also protected.

The Commission shall have the power to receive and redress in a time bound manner, the grievances and complaints that may be filed with the Commission by the students or their parents, in respect of the working of these institutions. The Commission shall have the authority to impose penalty upto five crore rupees, for contravention of the guidelines of the regulatory bodies relating to the privately managed educational institutions and any directions that may be issued by the Commission by virtue of the powers vested in it. As such, it has been decided to bring a legislation to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The....., 2010

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 8 of the Bill seeks to provide for Government loan to the Commission which is not quantified. Further, clauses 3, 4 and 6 of the Bill seek to establish Commission and to appoint Chairperson, members and other staff of the Commission. As such, the expenditure to be incurred on salary and allowances of the Chairperson, members and other staff of the Commission shall be met from the fund to be established under clause 8 of the Bill. Thus, there shall be no expenditure from the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 18 and 19 of the Bill seek to empower the State Government and the Commission to make rules and regulations respectively for carrying out provisions of this Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.
